

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 9/3/26

विषय:- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल
₹ 1,39,01,377 /- (एक करोड़ उनतालीस लाख एक हजार तीन सौ सतहत्तर रुपये) मात्र की
स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।
कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन
अध्यायना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 1,39,01,377 /-
(एक करोड़ उनतालीस लाख एक हजार तीन सौ सतहत्तर रुपये) मात्र की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26
में प्रदान की जाती है:-

क्र.	प्रमंडल का नाम	अध्यायना आई0 डी0	कार्य/योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय के लिए स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, मधुबनी	29932	Constructioo of Proposed Madarsa Darul Uloom Azizia at Chhaurahi, Babubarhi in Distt. Madhubani	397 / 23.11.2022	₹ 1,39,01,377 /- (एक करोड़ उनतालीस लाख एक हजार तीन सौ सतहत्तर रुपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय शीर्ष मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4225-अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वर्गो और अल्पसंख्यको के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-04-अल्पसंख्यको के कल्याण, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0104-बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना विपत्र कोड-03-4225040510104 के विषय शीर्ष-53-मुख्य कार्य-0104.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जायेगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी होंगे।
4. इस राशि के निकासी जिला कोषागार, मधुबनी से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 2227 (अ) पटना, दिनांक- 9/3/26

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।